











संघासन उठाने को लेकर सभी मुख्य राज्यों से बात हुई है। 13 अक्टूबर को कोटा का अनार है।

# वेतन काटने वाली कंपनियों पर अब कसेगा शिकंजा

## सख्ती ▶ केद्रीय श्रम मंत्रालय ने जारी किए कारवाई के आदेश

केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उपक्रमों से अनुबंधित फर्मों पर भी हो सकती है कार्रवाई

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

लोकतांत्रिक के नाम पर कर्मचारियों तथा मजदूरों को मार्च का पूरा वेतन देने में हीलाहकील करने वाली बौद्धिक व बौद्धिकता तथा सामाजिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ अनुबंध पर कार्य करने वाली इकाइयों और केंद्रों/उपक्रमों के साथ सख्ती का शिकंजा कम सकता है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय की ओर से केंद्रीय प्रमुखतापूर्वक के केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त इकाइयों के बारे में लिखावटीय पर करवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दरअसल, केद्रीय श्रम मंत्रालय को युवियों में अलावा कुछ कर्मचारियों को व्यक्तित्व लिखावटीय प्राप्त हुई है कि एक सरकारी कंपनी के लिए केंद्र/उपक्रम पर सेवाएं देने वाली उनका कंपनी में अब तक अनेक कर्मचारियों को मार्च का वेतन नहीं दिया है। पड़ने पर लोकतांत्रिक का हवालदार देकर मार्च का वेतन गैरेज जाने अथवा एक हफ्ते का वेतन काट कर दे दे दिए जाने को बात को का रही है।

बौद्धिक क्षेत्र उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अलावा रेलवे, छात्रों की मदद, प्रमुख पत्र, खानों और अंतर्राष्ट्रीय फ्लैट, एयरलाइन एक एयरपोर्ट उद्योग, पेट्रोलियम जैसे निर्यात उद्योगों से संबंधित इकाइयों तथा केद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि अंतर्गत हैं। उक्त वेतन को आम तौर पर कर्मचारियों को लोकतांत्रिक की अथवा का विशेष अकस्मात् देकर मार्च का पूरा वेतन दे रही हैं। परंतु उनके साथ अनुबंध पर कार्य करने वाली निजी क्षेत्र की कर्मियों/अन्य कर्मचारियों को वेतन देने में हीलाहकील कर रही है।

सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्री संजय गंगारकर के निर्देश पर कर्मचारियों में विशेष केंद्र/उपक्रम के कारण इस बार 15 अक्टूबर तक मार्च का वेतन दिए जाने की छूट दी जा सकती है। लेकिन जब इसके बाद भी लिखावटीय मिलती है तो करवाई नहीं मिलती है कि प्रमाणपत्रों के लोकतांत्रिक की घोषणा करते वक़्त सभी कर्मचारियों से लोकतांत्रिक के दौरान कर्मचारियों का वेतन न काटने की अपील की गई है।

# एफसीआई के एक लाख कर्मियों को मिलेगी कोरना बीमा सुरक्षा

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

कोरना महामारी के भयंकरताएं लागू देशगामी लोकतांत्रिक के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति में सख्ती व्यवस्था कर रहे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कर्मचारियों को सरकारी बीमा सुरक्षा बीमा देगी। एफसीआई के एक लाख से अधिक कर्मचारियों देशभर में अनाज को आपूर्ति करने में रत-रिजत नौकरी रहे हैं। इन्हें 10 लाख से लेकर 35 लाख रुपये तक की कोरना बीमा सुरक्षा दी जाएगी।

केंद्रीय उपभोग तथा खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने जोर देकर कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों को भी बीमा बीमा का लाभ दिया जाएगा। पासवान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय ने आने में महतता का पान्नावर प्रदर्शन किया है। लोकतांत्रिक के दौरान अनाज तक 750 तेल टैक्स में लगभग 21 लाख टन अनाज का वितरण किया है।

कोरना संक्रमण के बीमारों से बीमारों में खाद्यान्न आपूर्ति में खोसने घंटे लोग श्रमियों/उद्योगों को कोविड-19 से मोत होकर पर जीवन बीमा सुरक्षा कवर देने को प्रस्ताव किया गया है।

एश्विनी प्रसोद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतलराम को सलाह कर दिया

एश्विनी विक्रम बैक (एश्विनी) ने कोरना से लड़ाई में भारत के पर्याप्तों की सहायता करने हुए 220 करोड़ डॉलर वाली 16,500 करोड़ रुपये का बैंकगत प्रदान करने की शर्तों के अन्तर्गत एक प्रभाव से कोरना के अभाव में मिला, महिलाओं तथा श्रमियों को आर पत्र उपभोग से संबंधित तालम मदद के लिए 26 पत्रों को वित्त 1.70 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक राहत पैकेज शामिल है। असावधान ने कहा कि वे कल्प असावधान ने कहा कि एश्विनी को आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित है। इस समय हर स्वास्थ्य क्षेत्र को मदद तथा योग्य, असावधान क्षेत्र के मजदूरों, सूक्ष्म, चतुर् पत्र मालों उद्योगों तथा विविध उद्योगों को महामारी के प्रभाव से उबारने में सहायता के लिए 220 करोड़ डॉलर कर तालमाल सहायता देने की तैयारी कर रहे हैं।

# केंद्र ने आवंटित अनाज उठाने का राज्यों से किया आग्रह

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से राम विलास पासवान ने की बात

राज्यों के अनाज उठा लेने से एफसीआई को भी मिलेगी सख्ती

कोरना संक्रमण के दौरान सभी 80 करोड़ लोकतांत्रिकों को अनाज तौर पर अनाज उठा लेने से एफसीआई को भी मिलेगी सख्ती

# कोरना की दवा ही नहीं, खाद्यान्न निर्यात भी करेगा भारत

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

कोरना की दवा ही नहीं, खाद्यान्न निर्यात भी करेगा भारत

कोरना की दवा ही नहीं, खाद्यान्न निर्यात भी करेगा भारत

# कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत को 16,500 करोड़ रुपये देगा एडीबी

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

एडीबी प्रसोद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतलराम को सलाह कर दिया

एडीबी प्रसोद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतलराम को सलाह कर दिया

एडीबी प्रसोद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतलराम को सलाह कर दिया

एडीबी प्रसोद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतलराम को सलाह कर दिया

एडीबी प्रसोद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतलराम को सलाह कर दिया

# सवा लाख से अधिक ग्राहकों ने निकाला आंशिक पीएफ

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

एनपीएस से भी आंशिक निकाली होगी संभव

एनपीएस से भी आंशिक निकाली होगी संभव

# एनपीएस से भी आंशिक निकाली होगी संभव

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

एनपीएस से भी आंशिक निकाली होगी संभव

एनपीएस से भी आंशिक निकाली होगी संभव

# मोबाइल संदेश पर उपज खरीदने पहुंचेंगी एजेंसियां

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

कोरना वायरस की महामारी के चलते लागू लोकतांत्रिक से कृषि के द्वितीय संस्करण के लिए आयुक्तिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा।

उत्तर देशों की लड़ पर एएफएमए से उपजना होगा आसान

# कच्चे तेल के दाम को फिर मिलेगी थार

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

मैक्सिम सिटी, एफपीए

# चीन से 'डिस्टेंसिंग' भारत के लिए अक्सर

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

चीन से करोड़वार समेटने पर जलाने में की फल, अर्थिकी कर्मियों का प्रभाव से तैयार

# पीएम-केएस में पावर ग्राइड नुपये

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

पीएम-केएस में पावर ग्राइड नुपये

# कोरोना से लड़ने को आजीएआई देगी 21 करोड़

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

कोरोना से लड़ने को आजीएआई देगी 21 करोड़

# केपीएमजी का मत

राहुत पेंकेज काम किया तो वृद्धि दर 5.3-5.7 फीसद, अग्र वैश्विक मंदी जल्दी नहीं दूर हुई तो वृद्धि दर 4-4.5 फीसद, परंतु मांग व वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो विकास दर तीन फीसद से भी नीचे

# कई उद्योगों पर रहेगा खतरा का साया

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

कोविड-19 की वजह से देशभर में और बुनियाद के कई दूसरे देशों में लगा लोकतांत्रिक अगले कुछ हफ्तों में खराब हो जाएगा। लेकिन केपीएमजी की रिपोर्ट को मानें तो लोकतांत्रिक के खराब हो जाने का कई उद्योगों के लिए स्थिति सामान्य होने में बदल सकती है। रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के दौरान अनेक उद्योगों को खतरा सामने के लिए सामान्य रूप से उभरे हैं। रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के दौरान अनेक उद्योगों को खतरा सामने के लिए सामान्य रूप से उभरे हैं। रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के दौरान अनेक उद्योगों को खतरा सामने के लिए सामान्य रूप से उभरे हैं।

# पीएम-केएस में पावर ग्राइड नुपये

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

पीएम-केएस में पावर ग्राइड नुपये

# मांसम वितरण

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली

मांसम वितरण

















